









# संपादकीय

## आर्थिक बदहाली की सीधे जिम्मेदार सरकार

सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की नीति पर सचमुच अमल किया होता, तो साढ़े 36 लाख करोड़ रुपये लोगों की जेब में बचते। इतना पैसा उपभोग क्षेत्र में जाता। बेशक उससे बाजार को जो बल मिल सकता था। संसद में बताया गया है कि 2019-20 से 2023-24 तक केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पर कर/ उपकर/ शुल्क से 36,58,354 करोड़ रुपये वसूले। ध्यान दीजिए: 2024-25 के आम बजट में सरकार की कुल आमदनी का अनुमान 30,80,274 करोड़ रुपए लगाया गया है। 2019-20 में यह रकम 20,82,589 करोड़ रुपये थी। तो पांच साल में पेट्रोलियम पर टैक्स से सरकार ने उतनी रकम बटोर ली, जो इनमें से किसी एक वर्ष में उसे हुई आमदनी से ज्यादा है। इस दौर में बुनियादी मानव विकास से संबंधित योजनाओं के बजट में कटौती का सिलसिला भी चला है। तो वाजिब सवाल कि है सारी अतिरिक्त आय गई कहां? अब इसी हफ्ते कुछ संकेत संसद में दिए गए एक अन्य आंकड़े पर गौर करें: 2023-24 सरकारी बैंकों ने एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए के त्रश माफ कर दिए। पांच साल में ये रकम लगभग नौ लाख करोड़ रुपये बैठती है। इसके अलावा सरकार कह सकती है कि वह इन्प्रास्ट्रक्चर में पूँजीगत निवेश पर हर साल दस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रही है। देश में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव योजना पर भी बड़ी रकम खर्च हुई है। इसके अलावा 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में दी गई ह्यूट के कारण सरकार पर लाखों करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। बहरहाल, यह प्रश्न अनुत्तरित है कि की सरकार की इन प्राथमिकताओं से आम जन को क्या हासिल हुआ? जिस समय मध्य वर्ग का हास एक आम कथानक बन चुका हो और उद्योग जगत बाजार सिक्कड़ने की शिकायत कर रहा हो, तो यह अवश्य पूछा जाएगा कि आम लोगों की जेब से कॉरपोरेट सेक्टर धन ट्रांसफर करने की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है? कल्पना कीजिए कि सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की नीति पर सचमुच अमल किया होता। तब साढ़े 36 लाख करोड़ रुपये लोगों की जेब में बचते। इतना पैसा उपभोग क्षेत्र में जाता। उससे बाजार को जो बल मिलता, वह बेशक आर्थिक आंकड़ों में झालकता। तो क्या आज की आर्थिक बदहाली की सीधी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं जाती है?

# आलेख रैगिंग के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं

यागश कुमार गायल

---

साल के सत्रम कारावास और आधारक दड़ का प्रावधान था। दाढ़ों छात्रों को कॉलेज तथा हॉस्टल से निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। उसकी छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं पर रोक, परीक्षा देने या परीक्षा परिणाम घोषित करने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अन्यत्र उसके दाखिले पर भी रोक लगाई जा सकती है। रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने अथवा मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कॉलेज पर आर्थिक दंड लगाने के अलावा कॉलेज की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। अदालत के दिशा-निर्देशों के तहत किसी छात्र के रंग-रूप या उसके पहनावे पर टिप्पणी करके उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर उसका अपमान करना, उसकी नस्ल या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अभद्र टिप्पणी करना या उससे जबरन किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य कराया जाना रैगिंग के दायरे में सम्मिलित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग के खिलाफ एक समिति बनाने से लेकर संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने तक के सख्त निर्देश हैं, लेकिन रैगिंग के लगातार सामने आते मामलों को देख कर हैरानी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरिजीत पसायत, जस्टिस डी. के. जैन तथा जस्टिस मुकुंदकम शर्मा की खंडपीठ ने रैगिंग रोकने के लिए 11 फरवरी, 2009 को पहली बार बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि रैगिंग में मानवाधिकार हनन जैसी गंध आती है। खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रवन कमेटी की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा था कि रैगिंग रोकने में विफल शिक्षण संस्थानों की मान्यता रह करें। 2001 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पर रैगिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि शिक्षा परिसरों में रैगिंग रोकना शिक्षा संस्थानों का नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है, जिसे न रोक पाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा और ऐसे संस्थानों की संबंद्धता तथा उन्हें प्रदत्त सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त की जा सकती है। कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि रैगिंग के नाम पर दुर्व्यवहार रोकना कॉलेज प्रबंधन, प्राचार्य, अधिकारियों तथा छात्रावास अधीक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। एक विद्यार्थी कितने सपने संजो कर कॉलेज की दहलीज पर पहला कदम रखता है, और उससे भी अधिक उसके माता-पिता या अधिभावकों की आशाएं और अरमान उससे जुड़े होते हैं।

आईएफएफआई एक सार्थक फिल्म महोत्सव बन गया क्योंकि इसने भारतीय सिनेमा के इतिहास को दर्शाया और चार महान प्रतीकों - अक्षिनेनी नागेश्वर राव, राज कपूर, मोहम्मद रफी और तपन सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की

- सुभाष घड

इस साल का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महात्सव (आईएफएफआई) पिछले हफ्ते, 28 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। फिल्मों और इससे संबद्ध उद्योग से जुड़ी सभी चीजों के इस भव्य समारोह में, मुख्य आकर्षण भारतीय सिनेमा की चार महान हस्तियाँ - बहुमुखी अभिनेता अकिनेनी नागेश्वर राव, महान शोमैन राज कपूर, शाश्वत आवाज मोहम्मद रफी और प्रतिभाशाली कहानीकार तपन सिन्हा - के कार्यों का एक ऐतिहासिक उत्सव था। इन महान दिग्गजों ने अपनी असाधारण प्रतिभा एवं दृष्टिकोण से फिल्म उद्योग को गौरवान्वित किया और एक ऐसा अमित जाह बिश्वेगा

जिसने फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और दर्शकों की कई पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया है। उनकी विरासतें युगों-युगों तक गूंजती रहेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार राज कपूर एक अभिनेता, निर्देशक, स्टूडियो मालिक और निर्माता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों को हास्य एवं संवेदन के साथ चित्रित करती थीं, जिससे वे आम आदमी की आवाज बन गए। अपनी मार्मिक कथाओं और गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाने वाले तपन सिन्हा बंगल के एक निपुण फिल्मकार थे, जिनका काम अक्सर आम लोगों के संघर्षों को उजागर करता था। कलात्मकता को सामाजिक टिप्पणी के साथ मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने उनकी फिल्मों को कालजयी बना दिया है। अक्षिणी नागेश्वर राव, जिन्हें एनआर के नाम से जाना जाता है, तेलुगु सिनेमा की एक महान हस्ती थे। उन्हें उनकी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता एवं संशक्त अभिनय के लिए जाना जाता है। छह दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में उन्होंने अनगिनत अविस्मरणीय भूमिकाएँ निभाई। सबसे लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायकों में से एक, मोहम्मद रफी अपनी असाधारण आवाज और अभिव्यंजक गायन शैली के लिए प्रसिद्ध रहे। उनके सदाबहार गीतों ने विभिन्न पीढ़ियों और भाषाओं के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। एक फिल्म महोत्सव सही अर्थों में तभी सार्थक बन जाता है, जब वह अपने इतिहास पर गौर करता है और

A portrait of a man with grey hair and glasses, wearing a red sweater over a patterned scarf, sitting in a brown leather armchair. He is smiling slightly. The background shows a shelf with various trophies and awards.

इसकी शुरुआत को अद्वांजलि अर्पित करता है आईएफएफआई के 55वें संस्करण ने न केवल इन हस्तियों की सिनेमाई उपलब्धियों का उत्सव मनाया बल्कि फ़िल्म प्रेमियों की नई पीढ़ी को उनकी विरासत से परिचित कराने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। उनकी उल्लेखनीय विरासतों के शताब्दी वर्ष के मनाते हुए, इस फ़िल्म महोत्सव ने सावधानीपूर्वक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग और प्रदर्शनों वेमाध्यम से उनके अद्वितीय योगदानों को सामने रखा। रंगारंग उद्घाटन समारोह के मंच से, शताब्दी मनाने वाले इस महोत्सव ने पहले दिन से ही अपना रंग विखेरनाशुरू करदिया। एक शक्तिशाली ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति में एनआर, राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी और तपन सिन्हा की यात्रा का वर्णन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस यादगार शाम के काव्यात्मक स्पर्श देते हुए, अभिनेता बोमन ईरानी ने प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को समर्पित भावपूर्ण कविताएँ सुनाई, जो भारतीय सिनेमा पर उनके गहरे प्रभाव के रेखांकित करती हैं। इस समारोह का एक अनूठा आकर्षण इन हस्तियों को समर्पित एक विशेष डाक टिकट संग्रह का विमोचन था। इन चार दिग्गजों का प्रतिष्ठित छवियों को प्रदर्शित करने वाले, इस स्मारक डाक टिकट संग्रह ने सिनेमा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदानों को अमर बना दिया। बेहद सराहनीय बात यह रही कि इस महोत्सव में इन महान हस्तियों के परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और फ़िल्म उद्योग के

दोनों (मोहम्मद रफी का संगीत), और हारमोनियम (तपन सिन्हा) शामिल थी। इन फ़िल्मों के प्रदर्शन ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया और पीढ़ियों से चली आ रही उनकी शाश्वत अपील का उत्सव मनाया। ‘कारवां ऑफ़ सॉन्स’ नाम की एक संगीतमय यात्रा में राज कपूर और मोहम्मद रफी के 150 गीतों के साथ-साथ एप्नआर और तपन सिन्हा के 75 गाने प्रदर्शित किए गए। इस संगीतमय श्रद्धांजलि ने भारतीय सिनेमा के समृद्ध साउंडस्केप में उनके बेजोड़ योगदानों पर प्रकाश डाला। इस महोत्सव में ‘सफरनामा’नाम की एक प्रभावशाली प्रदर्शनी में इन चारों दिग्गजों के जीवन एवं करियर से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, यादगार वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। एन-एफ़ीसी और केंद्रीय संचार ब्यूरो ने अतीत एवं वर्तमान के बीच के अंतर को पाटे हुए, इन हस्तियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का अच्छा काम किया। मनोरंजन के क्षेत्र में किंज़, डिजिटल शोकेस और इंटरैक्टिव डिस्प्ले जैसी विषयगत गतिविधियां भी आयोजित की गईं। आईएफ़एफ़आई ने अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करने वाली द्विभाषी स्मारिका भी तैयार की। यह दुनिया भर से आने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से इन महान हस्तियों की विरासतों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। मीरामार समृद्ध तट पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुर्दर्शन पटनायक द्वारा बनाया गया एक अकर्षक रेत कला चित्रण इन महान सिनेमाई दिग्गजों के सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतीक है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता की मनमोहक रेत कला ने समृद्ध तट पर जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया और इन चारोंहस्तियों के कालातीत प्रभाव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके उल्लेखनीय योगदानों को भव्य एवं बेहद सार्थक तरीके से सम्मानित करने और उनके स्थायी प्रभाव को गरिमाएंवं श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि देने के सराहनीय प्रयास किए गए हैं। यह समारोहने न केवल उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाया बल्कि भारतीय सिनेमा की उस स्थायी भावना को भी मजबूत किया जिसे इन दिग्गजों ने आकार देने में मदद की। आईएफ़एफ़आई ने यह सुनिश्चित किया कि इन सिनेमाई हस्तियों की विरासत भावी कहानीकारों और दूरदर्शी लोगों का मार्ग प्रशस्त करती रहे।

**खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी.....**

प्रा. लल्न प्रसाद

अक्टूबर, 2024 में महागांड दर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई जो पिछले 14 महीने का सबसे ऊँचा स्तर है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4-6वीं की सीमा, जो अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित मानी जाती है, के ऊपर है, जो चिंता का विषय है। खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यह स्थिति ऐसे में है जब अधिकांश खाद्य पदार्थों की पैदावार कम नहीं हुई है। एक अनुमान के अनुसार वितरण की अव्यवस्था के कारण लगभग 20 लाख गल्ली उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिनको उसकी आवश्यकता है। फर्जी राशन कार्ड और राशन कार्ड के दुरुपयोग और काले बाजार में गल्ला बेचने की घटनाएं आम हैं। व्यापारियों और अमीर किसानों द्वारा गल्ले का स्टॉक बढ़ा कर कीमतों को प्रभावित करने पर सरकारी नियंत्रण कमजोर है। तेजी से बढ़ती आवादी के कारण खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ रही है। इसमें संदेह नहीं किंतु कीमतें उससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ खाद्य पदार्थों की मांग-पूर्ति में बढ़ा अंतर है, जिसके कारण उनकी कीमतों पर लगाम लगाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है जैसे दालें, मौसमी सब्जियां, फल आदि। शाकाहारी लोगों की थालियां ही महंगी नहीं हुई हैं, वे लोग भी जो मांस, मछली, चिकन आदि का सेवन करते हैं, बढ़ती कीमतों से त्रस्त हैं। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग की चीजें-घी, तेल,

साबुन, मसाल आर नकरान क आधिकाश सामान महाराष्ट्र होते जा रहे हैं, जो लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं कीमतों में बढ़ि के आंकड़े चाँकाने वाले हैं। सांख्यक एवं कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय के आंकड़े वे अनुसार भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सितम्बर, 2024 में बढ़ कर 5.4 9त्र हो गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.87 और 5.05त्र थी। अक्टूबर के आंकड़े और भौतिक निराशाजनक थे, महंगाई दर 6.21त्रपर पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 6.68त्र और शहरी क्षेत्रों वे लिए 5.62त्र थी। शहर वालों की अपेक्षा गांव के लोगों पर महंगाई की मार अधिक देखी गई। रिजर्व बैंक ने महंगाई की इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए अल्पकालीन ऋण दर को बदलने से मना कर दिया और सरकार का सुनिश्चित करने को कहा कि मुद्रास्फीति मार्जिन का चार प्रतिशत पर लाने की कोशिश करे। गेहूं की कीमत पिछले कुछ वर्षों से लगातार तेजी से ऊपर जा रही हैं। 2010 में गेहूं की औसत कीमत 1100 रुपये प्रति किंटल थी जो 2015-16 में 1450 पर आ गई। अक्टूबर, 2024 में यह 2700 के ऊपर पहुंच गई किसानों को इसका लाभ मिला किंतु उतना नहीं जितना अपेक्षित था क्योंकि इनपुट कीमतें खाद, बीज, डीजल भाड़ा, त्रम, सभी महंगे होते गए। सरकार ने 2024-25 के लिए गेहूं की न्यूनतम खरीद दर 2425 रुपये प्रति किंटल निर्धारित की जिसे किसान बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आम उपभोक्ता गेहूं की बढ़ती कीमतों से त्रस्त

है। गराबा म आटा गाला का कहावत चारताथ हो रहा है। दालें शाकाहारी खाने में प्रोटीन की मुख्य स्रोत हैं, उनकी कीमतें पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2020 में अरहर की दाल 80 रुपये प्रति किलो थी जो अब 180 प्रति किलो के लगभग है। अधिकांश दालों की खुदरा कीमत बाजार में 100 रुपये प्रति किलो के ऊपर है। दुनिया के दालों के कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा 25% है, किंतु यह मांग से कम है, आयात की आवश्यकता पड़ती है। सब्जियों की कीमतें तो मौसम के अधीन रहती हैं, जिन पर जलवायु परिवर्तन का असर बराबर देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से टमाटर, आलू, प्याज आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटा, दाल, सब्जी और मसालों की कीमतों में लगातार बढ़ते घर के खाने की थाली दिनोंदिन महंगी करती जा रही है, औसतन 10% प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि हो रही है। ढाबों से लेकर रेस्टोरेंट, होटल सभी में खाना महंगा होता जा रहा है। मांस, मछली, चिकन, अंडे की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। दूध उत्पादन में विगत वर्षों में अच्छी वृद्धि हुई है किंतु साथ ही कीमतें भी बढ़ी हैं। 2018-19 में भारत में दूध का उत्पादन 180 मिलियन टन के लगभग था जो 2023-24 में बढ़ कर 240 मिलियन के ऊपर पहुंच गया। इस बीच, दूध की सभी बड़ी कंपनियों ने कई बार कीमतों में वृद्धि की। देसी धी, खोबा और उनसे बनने वाली मिठाइयों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त रसोई गैस,

# एक साल बेमिसाल-मोहन का उद्योग-जाल

लेखक-सत्येद्र जैन

मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य के विकल्प प्रिंह हैं। यह किया है आर्थिक उद्योगों को बढ़ावा दें। उद्यम

पर्याय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश और उद्यमों को संवर्धित करने के लिए सर्वस्व उद्यम अपर्ण कर रहे हैं। एक समय वर्ष 2003 में प्रदेश की औद्योगिक विकास दर माइनस में थी। भाजपा की शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और स्वर्णीय बाबूलाल गौर की सरकार के परिश्रम और उद्योग हितैषी नीतियों के माध्यम से आज प्रदेश की औद्योगिक विकास दर लगभग 24 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लगभग 4 लाख करोड़ रुपए है। आज औद्योगिक क्षेत्र भी सैकड़ों हैं। भाजपा की मोहन सरकार का भविष्य में इस निवेश को 20 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री



विद्यमान  
समुचित दोहन कर  
था को,  
विकास को तीव्र  
करेगा यही कारण है कि उद्यमी  
डॉ मोहन यादव, प्रदेश में उद्योगों  
बिछाने के लिए संकल्पित हैं।  
औद्योगिक हब बनाने के लिये  
खुम्मती डॉ मोहन यादव ने पहली  
ग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री  
के साथ ही देश के बड़े महानगरों  
शो किए विदेशों से भी  
यों को आकर्षित कर निवेश लाने  
की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  
एसों से मध्यप्रदेश अर्थिक रूप से  
गा और युवाओं को रोजगार के  
अवसर मिलेंगे। मध्यप्रदेश को  
हब, मैन्यैफैकरिंग केंद्र बनाने

और रोजगार के  
मुख्यमंत्री डॉ मोहन  
प्राथमिकता है।  
इंडस्ट्री कॉन्क्लेव  
जबलपुर, सागर  
मुंबई, कोयबद्दर,  
में हुए रोड-शो निवाश प्रस्ताव प्राप्त  
रोजगार सृजन होगा  
लाने के लिये डॉ  
जाने को तैयार हैं  
हो या देश के बाहर  
मध्यप्रदेश अर्थिक  
देश की अर्थव्यव





संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी  
आम नागरिकों की समस्याएं

गरियाबंद (विश्व परिवार)। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने आज जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्र से आये लोगों की मांग, समस्याएं एवं शिक्षायात्रे सुनी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आज जनदर्शन में 77 लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और संवैधंत अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निराकार करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं, जैसे भूमि परिवाद, राशन कार्ड, पेंशन, पीएम आवास, वनअधिकारी पट्टा एवं विषयों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। संवैधंत विधायिकों का निष्पक्ष और सम्बद्ध समाधान किया जाए, ताकि आमजन को उनकी समस्या एवं शिक्षायात्रों का निराकार हो सके। जनदर्शन में ग्राम कोपरा के तुलनेर ने अन्तर्जातीय विवाह अनुदान हेतु, ग्राम पाण्डुका की मोंगारा बाई पटेल ने पी.एम. आवास दिलाने, ग्राम तरीं की रुखमड़ी बंजारे ने आवास की राशि दिलाने, ग्राम मजला कुमार के देवलाल ने जाति प्रगति पत्र, ग्राम हिवारत के परियोगी राशि ने द्रायसकल प्रदाय करने, ग्राम मैनपुर खुर्द के स्टेट्सवर साहू ने बिजली बिल में सुधार करने व भौतिक लाना, ग्राम सड़कपरसूली की केशरी बाई यादव ने दूरसे के बैंक में पैसा जाने हेतु, ग्राम साजापाली के मोहन पटेल ने पट्टा प्रदाय करने, ग्राम बिजली के रिवर्कुपर साहू ने जमीन की सीमांकार कराने, ग्राम मुमुक्षु अंगोरा कुमार यादव ने मुमुक्षु बीट में अन्यमुक्षु रखेन्द्र, ग्राम हरदाम के दशरथ ने नेशनल पेन्सन सिस्टम सर्विसिंग टिप्पिटेंट के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

पदमा के लिए वरदान बनी  
महतारी वंदन योजना

जगदलपुर(विश्व परिवार)। राज्य सरकार की नवीनतम महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्त्योगी साक्षित हो रही है। विकासखण्ड तोकापाल अंतर्गत एप्पडाल निवासी एकल महिला पदमा कच्छ इस योजना की सहायता को स्वयं के लिए वरदान मानकर सरकार को धन्यवाद देती है। पदमा राज्य सरकार की इस योजना की सहायता मिलने से भावुक होकर कहती है कि पति के गुरुरों के बाद उसे अपने भरण-पोषण के लिए केवल विधवा पेंशन ही सहायता लेकिन अब उक्त योजना की मदद उसे यानी में एक नई आस जानी दी है। पदमा ने बताया कि उसे सरकार की ओर से निरापत्र लोगों के लिए प्रावधानित अंतोदाय राशन कार्ड से हर महीने 10 किलोग्राम निःशुल्क चावल भी मिल रहा है। जिससे जीवन-यान में बहुत सहूलियत हो रही है। उसने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग घरेलू जलरत को पूरा करने के साथ थोड़ी राशि बचत कर रही है ताकि आड़े बक्क में काम आ सके। जात हो कि प्रदेश में महिलाओं के अधिक स्वावलंबन सहित उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुधूर करने और समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता को दूर करने एवं जगरूकता लाने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा अधिक स्वावलंबन एवं साक्षिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निष्पक्ष लिया गया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए  
महाविद्यालय में एकदिवसीय  
कार्यशाला का आयोजन

रामानुजारंज(विश्व परिवार)। शासकीय लर्सनसाय स्थानकोत्तर महाविद्यालय रामानुजारंज में प्रतियोगी परीक्षा व सीधीपोइससी के लिए छात्रहित को ध्यान में रखने हुए करियर मार्गदर्शन पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों द्वारा अपने करियर से संबंधित समस्याओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता छ. ग. राज्य स्पेशल चेयर स्पेशल प्रोफेसर 2024 में राज्य कर निर्वाचित पद पर चयापीत पंकज कुमार यादव के द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे-लक्ष्य निर्धारण, छ. ग. पीएससी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, तैयारी कब व कैसे करें। तैयारी के दौरान विषम परिस्थितियों का सामाना कैसे करें, पर मार्गदर्शन दिया गया, साथ ही अपने तैयारी के दिनों व तीन बार इंटरव्यू तक पहुंच कर सफलता प्राप्त करने तक का अनुबंध साझा कर विद्यार्थीयों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर कुछ कर दिखाने की जुनून पैदा किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में महाविद्यालय के विद्यार्थीयों से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्राचार्य शहा प्राध्यापक डॉ आर वी सोनवानी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्राचार्य सहा प्राध्यापक शनि कुमार धारी, राशयो के कार्यक्रम अधिकारी सहा प्राध्यापक रमेश कुमार खेरवार, प्रभारी सहा प्राध्यापक योगेश कुमार एवं अंतिथ व्याख्याताओं द्वारा विद्यार्थीयों के करियर संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अपना मार्गदर्शन दिया गया।

# पांच सदस्यों की जांच टीम कलेक्टर द्वारा गठन की गई थी

जांच टीम के समक्ष छात्राओं पुनः  
रो रोकर सुनाई अपनी आपत्ती

गरियाबंद (विश्व परिवार)। शासकीय उच्चतर हायपर सेकेंडरी विद्यालय मैनपुर में बहुचर्चित दो गुणों की लड़ाई की जांच के लिए जिलाधीश गरियाबंद के द्वारा पांच सदस्यों की जांच टीम गठित किया गया था जिसमें सदस्यों में कृपाल सिंह पर सहायक संचालक जिला गरियाबंद श्रीमती प. के लाडा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सङ्कालन परसुली श्रीमती तुसिं शानीग्रा प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल स्कूल छिंडीला बाय आर साहू प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुका बटी राय प्राचार्य शासकीय हाई हाई स्कूल कुरुभांड ने मैनपुर पहुंचक छात्रों व शिक्षकों से बारी बारी से पूरी पूछताज किया गया जांच की निष्कर्ष सामने तो नहीं आया है लेकिन खबर की असर में जांच टीम पहुंचे थे। साथ में जिला शिक्षा अधिकारी आंदं शाश्वत, एसडीएम मैनपुर पंकज डाहरे, एसटीओमी मैनपुर बाजीराव सिंह, श्याम चंद्रकर, महेश पटेल विकास खड़े शिक्षा अधिकारी, बी आर सी सी शिव कुमार नागे तहसीलदार गैंदलाल साहू थाना प्रभारी शिव



शंकर हुरा संजय नेताम जिला पंचायत उपाध्यक्ष लोकेश्वरी नेताम जिला पंचायत सदस्य दुलार सिन्हा मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण द्वारा व्याकृत कांगेस अध्यक्ष रुलसी गोलू पटेल नंदिकोशी चौबे मूकेश तालान ही स्थानीय उच्चतर हायपर संस्थान नहीं होने की दो गुणों की लड़ाई शात होगी अन्यथा लड़ाई शांत होने की संभावना नहीं बन रही है। देखना अब यह है कि जांच टीम के द्वारा क्या कर्कावाई की जाती है बेड टच करने

वाले शिक्षक पर क्या गाज गिर सकता है या जिला जायेगा यह जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन पालकों की मांग है कि विवादित लोगों को इस स्कूल से तकाल ही हटाया जाए। नहीं हटाए जाने पर विवाद की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और विवार्यों तनाव में रहेंगे क्योंकि उनकी परीक्षा नजदीक है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षायत में शासिल टीचर को ही प्राचार्य नियुक्त किया गया है यह न्याय संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आंदं शाश्वत से चर्चा करने पर कोई जवाब नहीं दिए। उचित जवाब नहीं दिए जाने के कारण अभिभावक आक्रोशित है

पांच सदस्यों की जांच केमेटी बनाई गई है उसमें बच्चों और शिक्षकों की बयान लिया गया है उसमें निष्कर्ष निकालकर जांच रिपोर्ट बनाइ जाएगी और दोषी विवादित लोगों के द्वारा जाएगी सबका बयान दर्ज कर लिया गया है आनंद शास्त्रवत् जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद

पालकों की ओर से यह प्रस्ताव किया गया है कि जो भी दोषी है उन कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाए और विवादित शिक्षकों को हटाया जाए।

योगेश शर्मा पालक

यहां शिक्षकों की ही लड़ाई हो रही है बाहरी लोगों की कोई दखल अंदाजी नहीं है शिक्षकों के कारण ही राजनीति हो रही है ललित ड्हाटे पालक

प्रकाश सिर पर है ऐसे में बेटियों की भवित्व को दृष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए दोषीयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे शैक्षणिक माहौल बेतर बनाने हेतु समूचित निष्पक्ष लेना बेहतर होगा हनीफेसेमन जिला इंचार्ज आम आदमी पार्टी

शिक्षकीय जगत को कलंकित करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही होनी चाहिए यदि जांच में शिक्षक दोषी हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए यदि यशवंत बघेल टीचर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रांतीय सचिव

## पंचायतों में कपड़ा प्रबंधन करें, नहीं तो होगी कार्यवाई : कलेक्टर

बीजापुर(विश्व परिवार)। सोमवार को जिला कार्यालय के द्वारा विभिन्न कार्यालयों को शुरू करने के संबंधित अवधारणा विभाग की समीक्षा बैठक ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पूर्ण आवासों की संख्या एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनांतर्गत सामुदायिक शैक्षालय निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने के कारण विकासखण्ड समन्वयक को कारण विताओं में विकास योजना को साथ देखते रहे। विकास योजना की विवरणों के बारे में जिला पंचायत निर्माण कार्यालय की विवरणों के साथ देखते रहे। विकास योजना के बारे में जिला पंचायत निर्माण कार्यालय की विवरणों के साथ देखते रहे। विकास योजना के बारे में जिला पंचायत निर्माण कार्यालय की विवरणों के साथ देखते र



